लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16 - 31 अक्तूबर, 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -52

“ आपकी खुशहाली तभी सार्थक कहलाएगी जब आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए अपना और अपनों का खूब खयाल रखें।

प्रदेश में बढ़ता निवेश, खुलते रोज़गार के नए आयाम

2

शिक्षा का नया अध्याय ‘ई एजूकेशन’

5

विकास के मार्ग

10

सुशासन के 9 साल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मनोज प्रभाकर

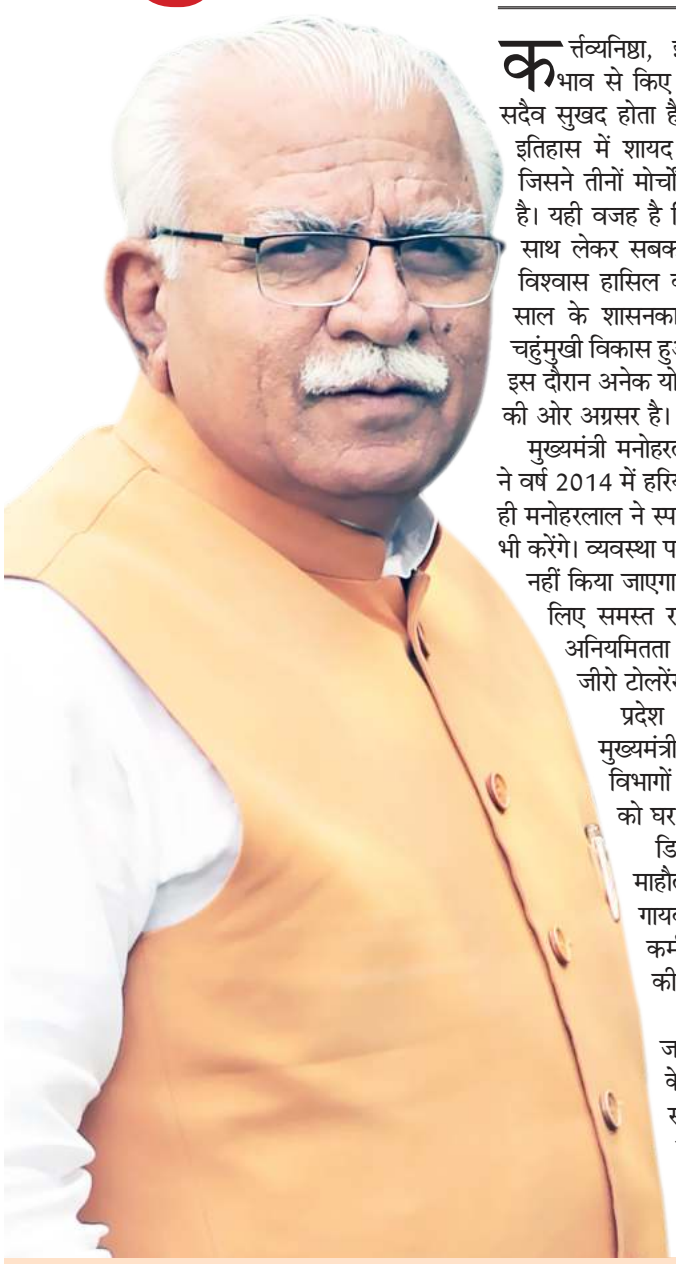

कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से किए गए कार्यों का परिणाम सदैव सुखद होता है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में शायद यह पहली सरकार है जिसने तीनों मोर्चों पर डटकर कार्य किया है। यही वजह है कि मनोहर सरकार सबका साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करने में कामयाब रही है। आठ साल के शासनकाल में बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ और प्रगति के अनेक आयाम स्थापित हुए। इस दौरान अनेक योजनाओं के बूते हरियाणा एक ‘आदर्श प्रदेश’ की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 में हरियाणा की बागडोर संभाली थी। कुर्सी संभालते ही मनोहरलाल ने स्पष्ट कर दिया था कि वे सुशासन के लिए कुछ भी करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी ‘वाद’ से समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा तथा पारदर्शिता के लिए समस्त राजकीय कामकाज ‘ऑन दा टेबल’ होगा। अनियमितता की कोई गुंजाइश न होगी तथा व्यवस्था में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

प्रदेश के लोगों का जीवन सहज व सरल हो, मुख्यमंत्री की ओर से इस पर विशेष ध्यान दिया गया। विभागों का कामकाज ऑनलाइन किया ताकि लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल सके।

डिजिटलाइज होने से सरकारी दफ्तरों का माहौल बदल चुका है। वहां से तथाकथित दलाल गायब हो चुके हैं। इतना ही नहीं कार्य के प्रति कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है ।

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा प्रदेश के सभी परिवारों को मिले इसके लिए राज्य सरकार अंतोदय की भावना से काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। इनको ‘आधार’ से जोड़ कर तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है।

गौरतलब है कि आठ वर्ष पूर्व जन प्रतिनिधियों के आगे-पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आवास व कार्यालय के बाहर जमघट लगा रहता था। पर्ची- खर्ची का माहौल था। फिर भी काम हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं थी। वर्तमान व्यवस्था में ‘बिन पर्ची बिन खर्ची’ से न केवल कार्य हो रहे हैं, नौकरियां भी मिल रही हैं। जन प्रतिनिधियों का ध्यान अब इधर-उधर न होकर अपने-अपने क्षेत्र के समान विकास पर है।

काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिलने से प्रदेश के युवक युवतियों में पढ़ने-पढ़ाने का जज्बा लौट आया है। जिसका परिणाम यह है कि हरियाणा के छोरे-छोरियां प्रति वर्ष अनेक प्रतिस्पर्धाओं में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अव्वल आ रहे हैं। खेल नीति का नतीजा यह है कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में हरियाणे का डंका बजा दिया है।

सूबे के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। युवाओं के लिए न केवल सरकारी सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं बल्कि निजी क्षेत्र में भी विशेष व्यवस्था की गई है। दुबई से लौटकर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब विदेशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बाहर की कंपनियां न केवल प्रदेश में निवेश करेंगी, यहां के युवाओं को नौकरियों के लिए आमंत्रित भी करेंगी। अति गरीब परिवारों के आर्थक उत्थान के लिए प्रदेश में जगह-जगह रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, ग्रामीण व शहरी विकास, उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, सड़क एवं यातायात, संस्कृति एवं साहित्य आदि हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश प्रदेश के लोगों में राष्ट्रभक्ति के भाव को बनाए रखने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहा।

जुबान के धनी एवं इरादों के पक्के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने ‘हरियाणा एक हरियावणी एक’ की नीति पर चलते हुए कभी भी, किसी भी मोर्चे पर किसी पूर्वाग्रह से समझौता नहीं किया। उन्होंने हर वाद से किनारा करते हुए पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना और समर्पण भाव से लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऐसी अनेक नई योजनाओं को प्रारम्भ कराया है जो आने वाले समय में प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगी।

बदल गए राजनीति के मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। विकास के दृष्टिगत समूचे देश व प्रदेश में पारदर्शी प्रणाली से व्यवस्था बदली हैं। राजकीय कार्यालयों के कामकाज में बड़ा परिवर्तन हुआ है।

न केवल सरकारी बाबूओं के काम करने के तौर तरीके बदले हैं, संगठन एवं निकायों के मुखिया, विधायक एवं सांसदों की कार्यशैली में भी सकारात्मक बदलाव हुआ है। जनता का जनप्रतिनिधियों के कामकाज में नाहक हस्तक्षेप लगभग बंद हो गया है तथा जनप्रतिनिधि भी बिना किसी जल्दबाजी के जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है तथा बिचौलिया राज खत्म हुआ है।

प्रदेश से जातिवाद, क्षेत्रवाद व भाई-भतीजावाद को समाप्त करके प्रत्येक वर्ग के कल्याणार्थ अनेकों योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। वर्तमान समय में अपराधियों को शरण नहीं दी जाती। उन पर दंडात्मक कार्रवाही के लिए न्यायपालिका को सिफारिश की जाती है। नशे से जुड़े अपराधियों से कड़ाई से निपटा जारहा है।

समाज को परिवार मानकर करते रहेंगे सेवा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उनका संकल्प है कि वे समस्त समाज को अपना परिवार मानकर यूं ही सेवा करते रहेंगे।

हरियाणा में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हरियाणा के लोगों को जात-पात या किसी अन्य धारा में नहीं बंटने देंगे। तभी उन्होंने हरियाणा एक-हरियाणवी एक का नारा आगे बढ़ाया।

लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदली जाए, उन्होंने इस पर निरंतर कार्य किया। 2014 से पहले हरियाणा की विशेष तरह की छवि थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने उस छवि का बदलने का पूरा प्रयास किया, जिसमें वे काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं।

गांवों में दूसरी बार चुने जाएंगे पढ़े-लिखे प्रतिनिधि

सूबे में पंचायती चुनाव की तैयारी हो गई है। यह दूसरा मौका है जब गांवों में पढ़े लिखे जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद सदस्यों, 3,081 पंचायत समिति सदस्यों, 6,220 सरपंचों व 61,993 पंचों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्तूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।

जिला फतेहाबाद के सदस्य जिला परिषद, सदस्य पंचायत समितियां, सरपंचों व पंचों के पदों के लिए चुनाव आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव (3 नवंबर) के मद्देनज़र अगले चरण में शेष जिलों के साथ करवाये जायेगे।

चुनाव की घोषणा होने के साथ ही उपरोक्त दस जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बाकी अन्य जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं।

पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

» 14 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

» 19 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन।

» 20 अक्तूबर को नामांकन की जांच।

» 21 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

» 21 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

» 21 अक्तूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी ।

» 30 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।

» 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।

» मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

» यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा।

» यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा।

संपादकीय

बेदाग सुशासन के आठ वर्ष

प्रशासन में आठ वर्ष की बेदाग़ निरंतरता और दामन पर कोई दाग़ नहीं, यही है वर्तमान मुख्यमंत्री एवं गठबंधन की सरकार के मुखिया का वैशिष्ट्य। अंत्योदय पर केंद्रित इस सरकार के मुखिया ने अपने अब तक के कार्यकाल में सभी वर्गों एव सभी पक्षों को सौहार्द और सुशासन की जो अनूठी सीख दी है, हरियाणा के राजनैतिक इतिहास में वह अप्रतिम मानी जाती है।

जहां तक विकास का प्रश्न है, कृषि, गांव, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शुद्ध पेयजल, सभी स्तरों की शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति, कौशल विकास आदि सभी मोर्चों पर एक समान गति से विकास के द्वार इन्हीं आठ वर्षों में खोले गए हैं।

इसके अतिरिक्त आईटी के क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने, संवाद की सभी खिड़कियां खोलने और पूर्ण पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने में इन आठ वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं।

प्रगति, विकास और नवनिर्माण के इन आठ वर्षों में वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में निरंतरता भी बनी हुई है और हर मोर्चे पर चाहे वह ग्रामीण विकास का हो, पर्यटन का या पर्यावरण का, निरंतर आगे बढ़ने का क्रम जारी है।

लोकतंत्र के सभी स्तम्भों पर समुचित रूप से ध्यान देने और वैचारिक स्तर पर सहमति/असहमति का रचनात्मक स्तर पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति वर्तमान की एक विशेषता रही है।

वर्तमान राज्य सरकार के इन आठ वर्षों में जो सुसंगठित विकास हुआ वह अभूतपूर्व रहा। प्राचीन समय से चली आ रही अनेक विसंगतियों को दूर करने का काम किया गया, वह भी बिना किसी वाद विवाद के। विपक्षी राजनीतिक दलों को भी कभी टिक्का टिप्पणी करने का मौका नहीं मिला।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

श्रमिक कल्याण

» श्रम विभाग के पोर्टल पर लगभग 52 लाख 30 हजार श्रमिक पंजीकृत

» मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में श्रमिकों के लिए अनुदान

श्रमसाधकों के बल पर आज हरियाणा देश में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। इसके चलते प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2020 में, श्रम विभाग को आवंटित 49 व्यापार सुधारों को पूर्ण रूप से लागू करके हरियाणा पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। हाल ही में गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के कल्याणार्थ कई नई घोषणाएं की।

इस समय श्रम विभाग के पोर्टल पर लगभग 52 लाख 30 हजार श्रमिक पंजीकृत है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लगभग 8 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 6 लाख से अधिक सदस्य सक्रिय हैं। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 17 लाख 47 हजार निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 906 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। 'अंत्योदय आहार योजना' के तहत 10 जिलों में श्रमिकों को 10 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत गरीबों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

श्रमिक कल्याण के लिए नई घोषणाएं: मुख्यमंत्री ने 60 लाख से ज़्यादा श्रमिक परिवारों के लिए 'मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना' की घोषणा की। इसके तहत ईएनटी, ब्लड, शुगर, ईसीजी आदि टेस्ट साल में एक बार निशुल्क होंगे। प्रदेश में 200 श्रम योगी क्लीनिक खोलने की भी घोषणा की। एडवांस लाइफ स्पोर्ट सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस प्रदेश में उपलब्ध होंगी। वहीं, सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएंगी। 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' में ऋण लेने के लिए श्रमिक परिवारों की अब गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होगी।

सहायता राशि में बढ़ोतरी: कार्य स्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर ढाई लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 4 लाख करने की घोषणा की। दिव्यांगता पर मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया गया है। दिव्यांगता में हर प्रकार की सहायता को दोगुना किया गया है। वहीं, दिव्यांग बच्चों की सहायता को ढाई हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। हर थैलेसीमिया के मरीजों की मदद करते हुए उन्हें 2,500 रुपए मासिक धनराशि दी जाएगी।

दैनिक वेतन में बढ़ोतरी: राज्य सरकार ने पहली जनवरी, 2022 से विभिन्न वर्गों के दिहाड़ीदार, मजदूरों के न्यूनतम, मासिक एवं दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की गई।

प्रदेश में बढ़ता निवेश, खुलते रोज़गार के नए आयाम

हरियाणा में देश व विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहन देकर आकर्षित किया जा रहा है। इससे राज्य में निवेश बढ़ने के साथ-साथ युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो रहा है। फ्लिपकार्ट समूह, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज समेत मारुति सुजुकी में निवेश की पहल करके राज्य में निवेश का दायरा बड़ा दिया है। समय-समय विदेश कंपनियां भी हरियाणा आकर निवेश के लिए हामी भर रही है। राज्य के औद्योगिक विकास का सुदृढ़ आधारभूत ढांचा व अन्य ऑनलाइन सहूलियतें भी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा से बेहतर कार्य कर रही हैं। वर्तमान सरकार ने आठ साल के कार्यकाल में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनते कार्य किए हैं। हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए इस रोड शो के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदाय की ओर से काफी उत्साह देखने का मिला।

उद्योगों को बढ़ावा देती नीतियां

» आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए दिनांक 29.12.2020 को ''हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020'' लागू की गई।

» उद्योगों की कास्ट आफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पालिसी बनाई।

» वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय नीतियां पेश की गई।

निर्यात में हुआ इज़ाफा

राज्य में निर्यात निरंतर बढ़ता जा रहा है और बड़े-बड़े उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात बढ़कर 1,74,572 करोड़ रुपए हुआ। इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं। प्रदेश में अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च 2022 के दौरान 1,672.43 करोड़ रुपए के निवेश से दस बड़े उद्योग लगे तथा इनमें 4,397 लोगों को रोज़गार मिला। फ्लिपकार्ट समूह मानेसर के पातली हाजीपुर में 140 एकड़ ज़मीन पर तीन मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है। एनरिक एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक आदि जैसे कई बड़े टिकट निवेश आकर्षित हुए। सोनीपत में, मारुति सुजुकी ने 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की मात्रा के साथ आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है। पानीपत में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज अपनी पेंट निर्माण सुविधा में 1,140 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पानीपत में आगामी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में विभिन्न नए व्यवसायों की परिकल्पना की गई है। एकल खिड़की के माध्यम से नए निवेश के समाशोधन के लिए लिया गया औसत समय 24 दिन था।

> प्रदेश में साढ़े पांच लाख रोज़गार के अवसर विदेशी व देश की कंपनियों द्वारा प्रदेश में किए गए निवेश से आया है। लगातार नई-नई कंपनियां निवेश के लिए हरियाणा में जमीनें खरीद रही हैं। हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद में से एक है। कंपनियों के आने से रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोज़गार मिलेगा। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) के आसपास लगातार नए-नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। सरकार नए-नए प्रोजेक्ट के लिए ई-भूमि, लैंड पुलिंग पॉलिसी व लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के माध्यम से जमीन खरीदेगी। वर्तमान में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से हजारों एकड़ भूमि खरीदी गई है।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

आधारभूत संरचना विकास निगम

राज्य में बड़े उद्योग स्थापित होने के लिए आधारभूत ढांचा विशेष मांग होती है। इसको देखते हुए राज्य में सड़कों व रेलवे लाइन को सुचारू किया गया। दशकों से अधूरे पड़े 135.65 कि.मी. लंबे कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2,345 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण किये गये। केएमपी के साथ पृथला (पलवल) से सोनीपत तक 5,566 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में तीन फूड पार्क बरही, राई व साहा में एच.एस.आई.आई.डी.सी द्वारा कुल 150 प्लाट अलाट किये गये। बड़ी, सोनीपत में 75 एकड़ भूमि पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ''मेगा फूड पार्क'' स्थापित किया जा रहा है। आई.एम.टी. रोहतक में स्थापित हो रहे मेगा फूड पार्क की परियोजना लागत लगभग 180 करोड़ रुपए है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

जब कोई व्यक्ति प्राइवेट व सरकारी नौकरी नहीं ले पाते तो उसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में ऐसे लोगों को छोटे, लघु व मध्यम दर्ज़े के उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें दी जाती है। राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''एम.एस.एम.ई. विभाग'' गठित किया गया। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 को ''हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020'' लागू की गई।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

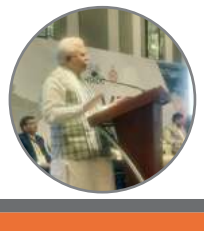

दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता किया है इनमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट, औद्योगिक पार्क, आईटी पार्क आदि परियोजनाएं शामिल हैं।

कृषि एवं पशुपालन तथा मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा से बागवानी, सब्ज़ी उत्पादन व कृषि क्षेत्र में नई-नई तकनीक की जानकारी लेने के लिए यूरोप गए डेलिगेशन के साथ स्पेन के होलसेल फल व सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड का दौरा किया।

खाद्यान्न आपूर्ति

» कोरोना काल में थामा गरीब परिवारों का हाथ
» राशन आवंटन प्रणाली को पारदर्शी बनाया

लागत के हिसाब से साल भर के अनाज का बंदोबस्त करना विशेषकर गांव देहात के हर गरीब परिवार की सालाना चिंता रही है। लामणी शुरू होने से पहले ही इसका गणित बनाया जाता है और परिवार के मजबूत सदस्यों को गेहूं कटाई के रण में उतर जाना होता है। कृषि क्षेत्र की यह प्राचीन परंपरा है जिसके बूते खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। जो गरीब परिवार कृषि से सीधे नहीं जुड़े होते उन्हें उस खाद्यान्न की कीमत का अर्जन करना होता है।

फरवरी-मार्च, 2020 में जब कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ तो उपरोक्त व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। अधिकांश फसलें मशीनों द्वारा काटी और सीधे मंडी में पहुंचा दी गई। इसके चलते खेतों में अपेक्षाकृत मजदूरों की संख्या कम रही। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब मजदूरों को काम नहीं मिला तो खाद्य संकट दिखाई देने लगा। सप्ताह या महीनाभर की खाद्य सामग्री लेकर बसर करने वाले गरीब परिवारों को भी चिंता वाजिब रही।

ऐसे संकट में केंद्र की मदद से राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का हाथ थामा। तत्काल खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। सुदूर इलाके में बैठे परिवार को भी इसका लाभ मिले इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए। आवंटन प्रक्रिया को सहज करने के लिए 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना शुरू की गई। 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना के तहत माह मई 2021 से मई 2022 तक 212502 लेनदेन के साथ हरियाणा पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा नया राशन कार्ड बनाने के लिए आनलाईन प्रणाली शुरू की गई। अब कोई भी व्यक्ति सरल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

बता दें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को दो श्रेणीयों में बांटा गया है। अन्त्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपए प्रति किलो की दर से रियायती दरों पर तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर वितरित किया जा रहा है।

कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के कुल 27 लाख एक हजार 77 परिवारों को 3 महीनों में लगभग 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी माह अप्रैल से नवम्बर 2020 तक उक्त लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं तथा चना दाल का वितरण किया गया है।

सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत बी.पी.एल./ए.ए.वाई. परिवारों को 20 रुपए की दर से 2 लीटर सरसों का तेल जनवरी, 2018 से मई 2021 तक वितरित किया गया तथा जून 2021 से प्रति परिवार 250 रुपए बी.पी.एल./ए.ए.वाई. परिवार के खातों में स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान कया गया। इस उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2022 तक 238.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई।

राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रत्येक मास एक किलोग्राम चीनी 13.50 रुपए प्रतिकिलो की दर से जनवरी, 2018 से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा केवल ए.ए.वाई परिवारों को प्रत्येक माह एक किलोग्राम चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है।

राशन आवंटन में कोई गड़बड़ी न हो जैसा कि पहले की सरकारों में होता रहा है, के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऑन लाइन किया गया है। आपूर्ति एवं आवंटन व्यवस्था को पूर्णतया पारदर्शी बनाने के लिए

जनवरी 2017 से शुरू से अंत तक कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने इस आवंटन व्यवस्था को और अधिक ईमानदार बनाने के लिए राशनकार्डों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। यह योजना पूरे प्रदेश में सफलता पूर्वक जारी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक मई 2016 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजना के तहत 7,30,960 गैस कनेक्शन गरीब परिवारों की महिलाओं को दिए गए हैं। इसके अलावा स्टेट फंड से 1,88,304 गैस कनेक्शन जारी किए हैं। इस तरह से प्रदेश में कुल 9,19,264 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश में सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसे अप्रैल, 2017 से 'कैरोसिन मुक्त राज्य' का दर्जा मिला है।

> आज हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात करने लगे हैं। परंतु उस दौर में खाद्यान्न की गुणवत्ता को भूलकर रासायनिक खादों का उपयोग कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया और इससे भूमि की उर्वरक शक्ति में भी कमी आई। आज उस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की अवधारणा को अपनाया जा रहा है।
>
> **मनोहरलाल, मुख्यमंत्री**

दिसंबर तक मिलेगा मुफ़्त राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन माह के लिए विस्तार दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक दिसंबर 2022 तक इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पहले की तरह प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हर माह पांच किलो राशन मिलेगा। देश में इसके तहत करीब 122 लाख टन राशन का विरण होगा जिस पर 44 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी।

हरहित स्टोर

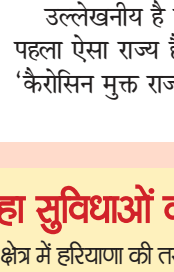

हरियाणा एग्रो का मकसद प्रदेश के हर गांव में हर हित स्टोर खोलकर गांव के ग्राहकों को माडर्न स्टोर देना है और युवा उद्यमियों के व्यापार को उनके ही गांव में बढ़ोतरी दिलवाना है । इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा सरकार स्टार्टअप्स के साथ-साथ करीब दर्जन भर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, एफपीओ, सरकारी सहकारिता संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान कर रही है। खादी, वीटा, हैफेड समेत इन समूह के उच्च स्तरीय प्रोडक्ट को भी हरहित स्टोर में रखे जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर खुल रहे इन स्टोर पर स्थानीय खाद्य पदार्थ भी बिक्री के लिए रखे जा सकेंगे।

योजनाओं का आधारः परिवार पहचान पत्र

केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं इससे पात्र व अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने में आसानी हुई है।

देश में 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार का डाटाबेस सिस्टम शायद ही किसी अन्य देश के पास उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन हमारी संस्कृति व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि परिवार केंद्रित है। इसी को समझते हुए वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने परिवार की पहचान के लिए भी नई पहल की है। इसके तहत, परिवार पहचान पत्र (मेरा परिवार-मेरी पहचान) की शुरुआत हुई।

योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए विभागों ने जमीनीस्तर तक अथक

प्रयास कर डाटाबेस एकत्र किया। प्रदेश में सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से देना सुनिश्चित किया जा रहा है। आज लगभग 150 योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से दिया जा रहा है। पीपीपी की बदौलत सरकार ने 37 लाख ऐसे ट्रांजक्शजन पकड़े जो गलत थे। उनके लाभ पर रोक लगाई गई, इससे करीब 1200 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

राशन कार्ड, वृद्धावस्थान पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। विवाह पंजीकरण को भी पीपीपी से जोड़ा गया है। इसके अलावा, जन्म व मृत्यु का डाटा भी पीपीपी से जोड़ रहे हैं, ताकि वास्तविक डाटा एकत्र किया जा सके।

योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवारों, जिनकी आय एक लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान की गई और उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन कर ऐसे परिवारों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और लगभग 32 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अलावा, अन्य पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने की प्रि या जारी है।

अंत्योदय परिवारों को मिल रहा सुविधाओं का लाभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है, वह अपने आप में उल्लेखनीय है।

आज प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पिछले 8 सालों में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में बड़ी बीमारियों के महंगे इलाज भी मुफ्त या सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रहे हैं। हर जरूरतमंद व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बनी है और जनमानस के लिए सही मायने में यह सरकार मनोहर सरकार साबित हो रही है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व स्कूल इत्यादि की संख्या में बढोतरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति , विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के लिए बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है। केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में साढ़े 15 लाख परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन अब प्रदेश के 22 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

स्वतः बन रही बुढ़ापा पेंशन

बुढ़ापा पेंशन के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति निर्धारित उम्र पूरी करता है, विभाग के अधिकारी एक महीने पहले उससे अनुमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेते है। इसके बाद उम्र पूरी होते ही पीपीपी के माध्यम से उसकी बुढ़ापा पेंशन स्वतः ही शुरू हो जाती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पिछले 4 महीनों में लगभग 12 हजार 763 नई पेंशन बनी है।

बनाए जा रहे पीले राशन कार्ड

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवारों की आय सत्यापन करके पीले राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में पीपीपी से राशन कार्ड बनाए हैं। भविष्य में इस अनूठी योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

महात्मा गांधी व नेल्सन मंडेला के नाम पर गठित गांधी- मंडेला फाउंडेशन व बदलाव के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार देने वाली संस्था इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहरलाल को गत दिनों सम्मानित किया गया।

पंचकूला के स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में हर खेल के अनुसार एक्सरसाइज प्लान बनाया जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन को माइक्रो लेवल पर दर्ज़ किया जाएगा और उसमें कैसे सुधार किया जाए, इससे जुड़ी सलाह दी जाएगी।

खुशहाल किसान, समृद्ध हरियाणा

» किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए दृढ़संकल्प सरकार

» बीजाई से फसलों के उचित दाम मिलने तक कृषि योजनाएं

वर्तमान सरकार हरियाणा के किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जैविक खेती को अपनाने पर विशेष जोर व रियायतें दी जा रही है। किसानों की फसलों का भी बीमा करके प्राकृतिक आपदा आने पर उचित मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि किसानों की आय दोगुनी हो और उन्हें उत्पाद को बेचने के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े। स्वयं ही किसान अपने उत्पाद की मार्केटिंग करें व मुनाफ़ा कमाएं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आठ साल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार निरंतर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधिकरण को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बाग लगाने, ड्रैगन फ्रूट व सिटरस फलों को उगाने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही है।

राज्य में 393 बागवानी कलस्टर, 13 एकीकृत पैकहाउस बनाए जा चुके हैं व 50 अन्य पैक हाउस निर्माणाधीन हैं। आने वाले पांच सालों में 500 और एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे। आने वाले समय में हरियाणा राज्य ताज़ा फलों एंव सब्ज़ियों की व्यवस्थित सप्लाई चैन व किसानों को सीधा कृषि बाज़ार से जोड़ने में एक अग्राणी राज्य होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

फसल की पैदावार में प्रकृति का विशेष योगदान होता है। कई बार मौसम की मार आंधी, तूफान, बारिश और ओले के कारण किसानों की फसल को बहुत नुक़्सान होता है। जिससे उबरने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। हरियाण सरकार ने किसान की इस पीड़ा को समझते हुए 2016 को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू की। इसके अंतर्गत खरीफ में धान, बाजरा, मक्का व कपास तथा रबी में गेहूं, सरसों, चना, जौ व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। खड़ी फसल में जलभराव ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है।

मेरा पानी मेरी विरासतः

पानी के बगैर जीवन नहीं जीया जा सकता। पानी को बचाना हर नागरिक का कर्त्तव्य है तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को उचित मात्रा में जल उपलब्ध करवा सकते है। वहीं, दूसरी ओर धान की खेती में भी बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना को शुरू किया गया। सरकार किसानों को धान की खेती छोड़ के अन्य विकल्पित फसल के उत्पादन के लिए 7,000 प्रति एकड़ की राशि किसान को प्रदान करती है। धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/कपास/खरीफ दलहन (मूंग, मोंठ, अरहर, उड़द, सोयाबीन, ग्वार)/ खरीफ तिलहन (तिल, मूंगफली, अरण्ड)/चारा फसलें/सब्ज़ियां/बागवानी/पॉपुलर/ सफेदा द्वारा विविधिकरण करने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत'योजना शुभारंभ किया गया है।

फसल अवशेष प्रबंधन पर सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध करवाये और इनको खरीदने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इतना हीं नहीं, बल्कि किसान इन अवशेषों की बिक्री करके आमदनी कमा रहे हैं और इनसे बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं। कई किसान इसे खेत में प्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक व्यक्तिगत श्रेणी के 41,331 किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध करवाये गये तथा 6,775 कस्टम हायरिंग सेंटर 80 प्रतिशत अनुदान पर स्थापित किये जा चुके हैं।

मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टलः

किसानों के भूमि रिकॉर्ड, फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभ के लिए बोई फसलों का पंजीकरण और सत्यापन के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल संचालित किया जा रहा है। रबी 2020-21 के दौरान पोर्टल पर 9,49,817 तथा खरीफ 2021 के दौरान पोर्टल पर अब तक 8,10,625 किसानों ने अपनी फसल पंजीकृत की है। रबी 2021-2022 के दौरान पोर्टल पर 25.04.2022 तक 8,97,225 किसानों ने 61,15,843 एकड़ फसल पंजीकृत की है।

हर खेत स्वस्थ खेत

भूमि का स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में राज्य सरकार के 'हर खेत स्वस्थ खेत अभियान' के तहत खेतों की मिट्टी की जांच का कार्य शुरू किया गया है। योजना के तहत चिन्हित खंडों में प्रत्येक खेत से मिट्टी के नमूने लेकर किसान को मृदा जांच रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा मृदा जांच हेतु 26 मई 2022 को ''हर खेत-स्वस्थ खेत'' पोर्टल लॉन्च किया गया।

भूमि का सुधार

जलग्रस्त एवं लवणीय भूमि का सुधार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 9,82,740 एकड भूमि जलग्रस्त एवं लवणीय समस्या से ग्रसित हैं। जिसमें लगभग 1,74,470 एकड़ भूमि गंभीर श्रेणी में आती हैं। राज्य में अब तक 28,930 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है।

किसानों को पुरस्कार

फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ नई तकनीक जैसे पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों, टिकाऊ कृषि आदि को अपनाने के लिए किसानों को नक़द पुरस्कार जो राज्य स्तर व जिला स्तर 5 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक के पुरस्कार दिये जाते हैं। वर्ष 2018 से शुरू 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की मांग है और हरियाणा में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस खेती से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश व राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए है। प्राकृतिक खेती पोर्टल शुरू किया गया।

फसल समूह विकास कार्यक्रम

ताज़े फलों व सब्ज़ियों के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इसके तहत 1,763 गांवों में 393 संभावित बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है। 34.58 करोड़ रुपए की राशि से कुल 10 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और 128 करोड़ रु. लागत की 50 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

फलों की खेती पर विशेष अनुदान

बागों की स्थापना से पानी की भी बचत होगी होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है। जिसमें पौधा रोपण के लिए 50,000 रुपए एवं ट्रैलिसिंग सिस्टम (जाल प्रणाली) के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ है। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा का लाभ ले सकता है।

मधुमक्खी पालन नीति

हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य है और यह नीति सुपर मधुमक्खी बक्से, रानी मधुमक्खी, खाद्य ग्रेड बाल्टी इत्यादि के माध्यम से गुणवत्ता शहद पर ध्यान देने के लिए माह सितंबर 2021 में 10 वर्षीय कार्य योजना लागू की जा चुकी है। विभिन्न हस्तक्षेपों के साथ शहद का उत्पादन 2030 के अंत तक 4,500 मीट्रिक टन से बढ़कर 15,500 मीट्रिक टन हो जाएगा। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), रामनगर, कुरुक्षेत्र में 2.64 करोड़ रुपए की लागत से शहद व्यापार केंद्र (एचटीसी) स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

उत्कृष्टता केंद्र

हरियाणा बागवानी प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना देश में सबसे आगे है। अब तक ग्यारह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2021-22 में इन उत्कृष्टता केंद्रों में 320 किसानों को शामिल करते हुए 64 विलेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ जोड़ा गया, इस वर्ष के अंत तक 335 किसानों को शामिल करते हुए 67 विलेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ और जोड़ा जाएगा।

हाई-टेक बागवानी को बढ़ावा

राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए वर्टीकल खेती के रूप में नवीन तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा संरक्षित खेती पर सहायता और प्रौद्योगिकियां प्रदान करने में सबसे आगे है। इस वर्ष अब तक कुल 11 एकड़ में नेट हाउस और 13 एकड़ में बांस स्टेंकिग लगाई जा चुकी है। राज्य में नई तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और हाईटेक संरक्षित संरचनाओं के लिए किसानों और उद्यमियों को 35 प्रतिशत सहायता के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। अगले साल प्लास्टिक और वर्टीकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी के तहत 10,000 एकड़ कवर करने का लक्ष्य है। बटन मशरूम में हरियाणा अग्रणी राज्य है। प्रदेश में मशरूम की नई किस्में बेहद सफल हुई हैं। मशरूम की खेती को और बढ़ावा देने के लिए कम और मध्यम लागत की 200 से ज़्यादा परियोजनाओं को अनुदान दिया जाएगा।

भावांतर भरपाई योजना

फसल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान/जोखिम को कम करने, बाजरा किसानों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए 2021 के दौरान भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इसमें 21 फलों और सब्ज़ियों का मूल्य तय कर किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है।

गन्ने का सर्वाधिक भाव

सीज़न 2021-22 में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा कुल 755.50 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई तथा कुल 71.48 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन तथा चीनी रिकवरी 9.47 प्रतिशत है। 2021-22 में गन्ना उत्पादक किसानों को देश में सर्वाधिक 362 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भाव दिया जा रहा है । उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न चीनी मिलों को 464.97 करोड़ रुपए की राशि, सब्सिडी के तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों को सीधे उनके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की गई।

हरियाणा में आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र- 47 में उपचुनाव और मतदान 3 नवंबर, 2022 को होगा।

मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहला 'चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा अवार्ड' दिया।

शिक्षा का नया अध्याय 'ई एजूकेशन'

» डिजिटल क्रांति से खुले शिक्षा के नए आयाम

» प्रतिभाओं को तराशती कौशल आधारित शिक्षा

संगीता शर्मा

किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता 5 एस पर आधारित होती है, यानी- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। राज्य सरकार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। रोज़गारपरक शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को अधिक तवज्ज़ो दी जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को लागू करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है। इस नीति के तहत कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की सिफारिश को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गया। इसके तहत 110 विद्यालयों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करना है।

हरियाणा कौशल विकास मिशन :

सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटल तौर पर दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने के काबिल बनाने के लिए अनेक नई पहल की हैं। इनसे हमारे युवाओं में एक नये उत्साह का संचार हुआ है। युवाओं को परम्परागत व्यवसायों के साथ-साथ आधुनिक व्यवसायों में भी प्रशिक्षण देने के लिए 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' बनाया गया है। इसके तहत लगभग 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

उच्चतर शिक्षा का प्रसार

राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई को भी अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा में कुल 177 राजकीय महाविद्यालय है। सत्र 2022-23 में चार नये महाविद्यालय खोले गये है। इनमें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 72 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के है। राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले है या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, परंतु इस महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर पाए है, उनके शिक्षा ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय। इससे लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचेगा। छात्राओं की स्नातक स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस माफ की गई।

विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग पहल

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का है और इसने पढ़ाई को बहुत आसान कर दिया है। राज्य में डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी/ई-ग्रंथकोष का शुभारंभ किया गया। उपयोगकर्ता के लिए मुफ़्त ई-संसाधनों जैसे लगभग 6 करोड़ ई-बुक्स, 3 लाख वीडियो और ऑडियो, 10 लाख पत्रिकाएं, 23 हजार पाठ्क्रम सामग्री, 6 हजार ई-पत्रिकाएं और 55 ई-समाचार-पत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए गए।

'ई-अधिगम ' योजना के अंतर्गत 5 मई, 2022 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों व उन्हें पढ़ाने वाले को टेबलेट्स वितरित किए जाने की शुरुआत की गई। इस टैब में ही उनकी ई-किताबें प्राप्त होंगी। ये टैबलेट भविष्य का क्लासरूम बन जाएगा। 'सुपर 100' कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आई.आई.टी./जे.ई.ई./एन.ई.ई.टी. इत्यादि परिक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है।

> हरियाणा अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस बार के बजट में अकेले 20 हजार करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें स्वरोज़गार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटल तौर पर दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने के काबिल बनाने के लिए अनेक नई पहल की हैं। युवाओं को परम्परागत व्यवसायों के साथ-साथ आधुनिक व्यवसायों में भी प्रशिक्षण देने के लिए 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' बनाया गया है।
>
> **-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री**

तकनीकी शिक्षा से खुले नये अध्याय

वर्ष 2021-22 में राजकीय बहुतकनीकी संस्थाएं एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश में मुख्य सुधार किया गया है। पात्र छात्रों की प्लेसमेंट में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये है। चार राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये गये है। राष्ट्रीय परियोजना के तहत एनआईएलईटी कुरुक्षेत्र, आईआईएम रोहतक, एनआईडी उमरी और विस्तार केंद्र आईआईटी दिल्ली, सोनीपत में तथा राज्य परियोजना के तहत एसआईईटी झज्जर, एसआईईटी रेवाड़ी, एसआईईटी नीलोखेड़ी स्थापित हो चुके है। उन्नत प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र 50 करोड़ रु. के निवेश के साथ दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय साईस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में एआईसीटीई द्वारा स्थापित किया जा रहा है। गूंगे व बहरे व्यक्तियों के लिए राजकीय बहुतकनीकी पंचकूला में महाऋषि अष्टावक्र केंद्र की स्थापना की गई है।

सृजित होते रोज़गार

» रोज़गार के इच्छुक लगभग 8.62 लाख प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाइट के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है।

» निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य भर में प्रति वर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम दो रोजगार मेले या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य है। रोजगार विभाग, हरियाणा द्वारा विभागीय पोर्टल पर आनॅलाइन जॉब फेयर मोड्यूल संचालित कर दिया गया है। 30 जून 2022 तक कुल 90,090 प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया।

» हरियाणा के बेरोज़गार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक रोज़गार पोर्टल 15 जुलाई, 2020 से शुरू किया गया।

» हरियाणा के 40,65,572 अभ्यार्थियों के डेटा को रोज़गार पोर्टल पर पोर्ट किया गया है। रोज़गार पोर्टल पर अब तक 14,574 नियोजकों और 27 एग्रीगेटरों को लाया जा चुका है।

» ''सक्षम युवा योजना'' के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000 रुपए तथा पात्र स्नातक बेरोज़गारों को 1,500 रुपए तथा 10+2 पास बेरोजगारों को 900 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने के एवज में 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत अक्तूबर, 2014 से अब तक लगभग 3.85 लाख सक्षम युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए तथा 1,216.06 करोड़ रुपए बेरोज़गारी भत्ता व 781.92 करोड़ रु. मानदेय के रूप में वितरित किए गए।

» विभाग, हरियाणा राज्य की एवं अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी हेतु हरियाणा के 50,000 मेधावी युवाओं को मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान कर रहा है।

कौशल विकास ने बढ़ाई रोज़गार की आस

आई.टी.आई. की इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने वाली लड़कियों को 500 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। सत्र 2021-22 में 8 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किये गये है। युवाओं की स्किल निखारने के उद्देश्य से गांव पन्नीवाला मोटा (सिरसा) में हरियाणा का पहला ''मॉडल कौशल केंद्र'' शुरू की गई। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 13,018 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण किया गया। सत्र 2021-22 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतू 11 नये व्यवसाय आरम्भ किये गये है।

प्रदेश ने ओडीएफ स्थायित्तव तथा ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों पर अक्तूबर माह को 'सी योरसेल्फ इन साइबर' थीम के साथ साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है।

विकसित गांव - स

मनोज प्रभाकर

महात्मा गांधी ने कहा था, देश की आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास नितांत आवश्यक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा तथा गांव में कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना होगा ताकि रोजगार के प्रचूर अवसर उपलब्ध हो सकें। गांवों का विकास होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा।

हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के हर भाग में विकास कार्य हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ खड़ी रहने वाली राज्य सरकार ने लोगों का जीवन सहज व सरल कैसे हो इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़कों का समुचित इंतजाम किया गया है। यही वजह हैं कि लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन काफी कम हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 30 जून 2022 तक कुल 16122.96 करोड़ रुपए की राशि जारी

की गई।

स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर 'दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना' के तहत तीन वर्षों में 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में इसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें से 50 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। विकास कार्यों में तेज़ी के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव के लिए एक नई योजना 'स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना ' वर्ष 2016-17 से 2020-21 लागू है।

विकास को लेकर पंचायतों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा लाने के लिए जनवरी, 2018 में '7-सितारा ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना' शुरू की गई थी। जिसमें लिंगानुपात सुधारने के लिए गुलाबी स्टार, शिक्षा को बढ़ावा व ड्रापआऊट रोकने के लिए नीला, स्वच्छता के लिए सफेद, शांति व भाईचारे के लिए नारंगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए हरा, सुशासन के लिए गोल्डन तथा सामाजिक सहभागिता के लिए सिल्वर स्टार दिये जाते हैं ।

गांव के विकास में आधुनिकता सजे इसके लिए राज्य सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शिक्षा निर्धारित की। सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए मैट्रिक, अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला पंच का पांचवीं पास होना अनिवार्य किया गया। पढ़ी लिखी पंचायतों के होने की झलक बहुत से गांवों में देखने का मिल रही है।

स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में क्रांकिारी परिवर्तन हुए हैं। 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत प्रदेश में 2014-15 से अब तक 74,0504 व्यक्तिगत शौचालयों व 5910 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। 22 जून, 2017 से हरियाणा के सभी ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त हैं।

जन प्रतिनिधि विकास में रूचि लें इसके लिए कुछ मानदेय तय किए गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपए, उपाध्यक्ष का 7,500 रुपए तथा सदस्य का 3,000 रुपए मासिक किया गया है। पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 7500 रुपए, पंचायत समिति उपाध्यक्ष का 3,500 रुपए तथा पंचायत समिति सदस्य का 1,600 रुपए मासिक किया गया। सरपंच का मानदेय 3,000 रुपए, पंच का 1,000 रुपए मासिक किया गया है।

अमृत सरोवर योजना

ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अति महत्त्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना पर कार्य अपनी गति पर है। इस योजना के कार्यान्वित होने से पेयजल एवं सिंचाई जल की उपलब्धता में मदद मिलेगी। इनसे न केवल भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा, गांवों का सौंदर्यीकरण भी होगा।

हरियाणा सरकार ने योजना के तहत अपने तय लक्ष्य से अधिक अमृत सरोवर बनाकर उपलिब्ध हासिल की है। 15 अगस्त, 2022 तक प्रदेश में 418 अमृत सरोवर बनाये जाने थे, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 557 अमृत सरोवर बनाये जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाये जाने हैं।

4811 तालाबों का डिजिटल सर्वे करवा लिया गया है और उसके बाद 3404 की शक्लोसूरत बनाने के लिए कार्य आवंटित कर दिया है। 2737 तालाबों की ड्रॉइंग्स बनाने के बाद अनुमानित लागत तैयार की जा रही है। 268 ड्रॉइंग्स का सत्यापन किया जा रहा है। केवल 399 ड्रॉइंग्स प्रि याधीन है।

तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन : तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प करने के साथ-साथ गन्दे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 23.10.2018 को किया गया था। प्रदेश में कुल 19,170 तालाब (ग्रामीण 18 308 तथा शहरी 862) हैं। इन सभी तालाबों को जियो-मैप और जियो-टैग किया जा चुका है।

मिशन अमृत महोत्सव के अनुसार प्रत्येक जिले में 75 तालाबों की दर से 1650 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया है जिनके वर्ष 2022-23 में पूरा होने की संभावना है। अब तक 2362 गांवों के कुल 5658 तालाबों को अगले तीन वर्षों में ठीक करने का ज़िम्मा लिया गया है। जिसमें हरियाणा वाटर रिसोर्सेस अथारिटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार रेड और पिंक ज़ोन के अंतर्गत आने वाले 612 गांवों में 1103 तालाब हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा के दो शहरों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गुरुग्राम को 29वां और रोहतक को 56वां रैंक मिला है।

कृषि मंत्री जे.पी दलाल और विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए यूके के एक प्रमुख संस्थान क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय, बेडफोर्ड का दौरा किया।

सशक्त हरियाणा

पेयजल

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 75.40 करोड़ रुपए की लागत से 48 नहर आधारित व 12 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए। 317.05 करोड़ रुपए की लागत से 1310 नलकूप तथा 198 बूस्टिंग स्टेशन शुरू। 1547.83 करोड़ रुपए की लागत से 9765.32 किलोमीटर लम्बी पाइप लाईनें बिछाई गई।

महाग्राम योजना के अन्तर्गत 34 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्त्रोतों में बढ़ोतरी तथा इतने ही गांवों में मल निकासी (सीवरेज) सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। गांव सौतई जिला फरीदाबाद व नाहरपुर जिला गुरुग्राम में महाग्राम योजना की परियोजना चालू कर दी गई है।

जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है। हरियाणा राज्य में 6 अप्रैल 2022 तक सभी जिलों में 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित।
- सभी जिलों में अब तक 1856 ग्राम सचिवालय राज्य मे स्थापित किये गए।
- राज्य में 1123 व्यायाम शालाओं के लिए 362.87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत ।
- पंचायती राज संस्थाओं में मतदाताओं को उनके निर्वाचित प्रतिनिधि हटाने का अधिकार दिया गया।
- बिजली बिल व सहकारी संस्थानों के डिफाल्टर तथा जिनके घर शौचालय नहीं, नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव।
- अपराधिक मामलों तथा कम से कम 10 साल कैद की सज़ा के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक।
- ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट।
- चौकीदार का मानदेय 7,000 रुपए व वर्दी भत्ता 2,500 रुपए किया गया।
- ग्रामीण चौकीदार की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष
- श्मशान घाटों के सुधार हेतु 73 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि जारी ।

आजीविका मिशन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत अक्तूबर, 2014 से जुलाई, 2022 तक 3292.87 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 782.33 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा में 125 लाख कार्य दिवसों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अक्तूबर, 2014 से जुलाई, 2022 तक कुल 52363 नये स्वयं सहायता समूहों के गठन पर कुल 317.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनके अलावा 2014-15 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत गरीब युवाओं के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के लिए अक्तूबर, 2014 से जुलाई, 2022 तक 152.43 करोड़ रुपए खर्च किए तथा 33920 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्य' म अब 7 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अक्तूबर, 2014 से जुलाई, 2022 तक कुल 154.08 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। लगभग 80.59 करोड़ रुपए के बजट के साथ वर्ष 2021-22 में कुल 9 स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाएं आगामी 5 वर्षों में 5 जिलों में ि यान्वित की जाएगी।

विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अक्तूबर, 2014 से जुलाई, 2022 तक 203.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर, स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 21 फरवरी, 2016 को 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कुल चयनित 10 कलस्टरों में 150 गांवों में से 1087 गांवों में 2016 से जुलाई, 2022 तक कुल 594.47 करोड़ की राशि खर्च कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

लाल डोरा मुक्त

आंवटन एवं बंटवारे के मकड़जाल में फंसी गांवों की जमीन को उक्त योजना से बड़ी राहत मिली है। चप्पा-चप्पा जमीन की निशानदेही हो गई है। अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि किस जमीन का कौन मालिक है। ऐसा पहली बार हुआ है। कहा जा सकता है कि प्राचीन समय से चले आ रही भू दुविधा समाप्त हो गई है।

राज्य के 44,212 वर्ग किमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीआईएस मानचित्र प्रणाली की परियोजनायें पूरे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई। यह प्रणाली भूमि के सटीक सीमांकन तथा परिवर्तनों का पता लगाने और अति' मणों की पहचान करने में सहायता करेगी।

स्वामित्व परियोजना के अंतर्गत 26 जनवरी, 2020 को सिरसी गांव लाल डोरा मुक्त होने वाला देश का सर्वप्रथम गांव बना। प्रदेश में 11 अक्तूबर, 2020 को प्रदेश के सभी 22 जिलों के 221 गांवों में से प्रति जिला एक गांव को लाल डोरा मुक्त करने का उद्घाटन किया गया था। इसके अंतर्गत अब भू-स्वामियों को मालिकाना अधिकार एवं संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज़ होने के कारण अचल संपत्ति पर ऋण की सुविधा मिल सकेगी।

अब तक राज्य के 6260 गांवों में लाल डोरे में मानचित्रण का कार्य तथा डाटा प्रा' या भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 6 जुलाई 2022 तक 6248 गांवों के लाल डोरा स्थित 23.65 लाख से अधिक अचल सम्पत्तियों के भू-स्वामियों को मालिकाना अधिकार तथा पंजीकृत टाइटल डीड (भू-संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज़) वितरित की जा चुकी हैं।

वर्तमान में हर भू-स्वामी किसी भी समय अपनी सम्पतियों और भू-रिकार्ड का ब्यौरा आनलाईन प्राप्त कर सकता है। इसमें दस्तावेजों का पंजीकरण, इंतकाल, जमाबंदी रिकार्ड का रख रखाव, ई-खसरा गिरदावरी, रोजनामचा व स्वामित्व रिकार्ड की नकल आदि जारी किये जाते हैं ।

सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई ज़मीन की खरीद के लिए वर्ष 2014 से ''ई- भूमि वैब पोर्टल'' शुरु किया गया। ई-भूमि वैब पोर्टल पर 12663 किसानों ने लगभग 28039 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। इस पोर्टल के माध्यम से 60 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसके लिए भू स्वामियों ने स्वेच्छा से लगभग 924 एकड़ भूमि देना स्वीकार किया है।

पेंशन

हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। सरकार द्वारा 27.00 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभपात्रों को परिवार पहचान पत्र से भी जोड़ा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बजट 7827.75 करोड़ रुपए था। जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 9337.40 रुपए हो गया है।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति यों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, दिव्यांग, बौना व किन्नर की पेंशन 2,500 रुपए मासिक की गई है। लाडली पेंशन योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु तक के माता-पिता, जिनकी सन्तान एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हों और वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, की पेंशन राशि भी 2,500 रु. मासिक की गई है।

विस्थापित कश्मीरी परिवारों को 1,000 रुपए प्रति सदस्य एवं अधिकतम 5,000 रुपए प्रति परिवार वित्तीय सहायता दी जा रही है। अनुसूचित जाति,विमुक्त /टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की बेटी के विवाह पर मिलने वाली शगुन राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 71,000 रुपए की गई है। अनुसूचित जाति के अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को मिलने वाली शगुन राशि 11000 रु. से बढ़ाकर 31,000 रु. की गई।

कृषि विभाग के मुताबिक किसान खराब फसलों की जानकारी ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करें। अधिकारी किसानों को प्रोत्साहित करें कि वे जल्द से जल्द अपने नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर भरें, ताकि किसानों को जल्द मुआवज़ा मिल सके।

किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें किसानों को पंजीकृत फसलों की संख्या, खरीद के लिए फसल की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी मिलेगी।

सेहत

» ऐलोपैथी के समानान्तर आयुष को बढ़ावा
» स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर हो रहा विस्तार

मुख्यमंत्री मनोहरलाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में जिस शिद्दत से कार्य हुए हैं वे अपने आप में उल्लेखनीय हैं। इसका उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला था जब स्वयं मुख्यमंत्री ने दिन रात एक कर अधिकारियों तथा मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर महामारी पर नियंत्रण पाने का काम किया था। सेहत के मामले में उन्होंने कभी किसी ढिलाई के साथ समझौता नहीं किया। इस क्षेत्र में निरंतर कार्य हुए हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व स्कूल इत्यादि की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए, जिससे एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1735 हो गई है।

आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया

राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के लिए बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है। केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में साढ़े 15 लाख परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया जिसके कारण अब प्रदेश के 22 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

- मनोहरलाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर आईसीयू की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार-2021 से सम्मानित किया गया है।

करनाल के कुटेल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्थापित की जा रही है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी। इस युनिवर्सिटी में 750 बैड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अनुसंधान विभाग भी होंगे।

प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। जिसमें, भिवानी में पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज, जींद में राजकीय मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के छायंसा में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज, नारनौल के कोरियावास में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कैथल, सिरसा व यमुनानगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज, गुरुग्राम में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज चरण-2 शामिल है। इसके अलावा, रेवाड़ी में एम्स भी बनाया जा रहा है, जो हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में 6 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इन पर लगभग 194 करोड़ रुपए की लागत आएगी। घोषणा के अनुरूप इन सभी जिलों में बनाये जा रहे कॉलेज का कार्य 85 से 88 प्रतिशत तक पूरा हो चूका है।

ढांचागत विकास के लिए 110 करोड़ स्वीकृत

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस मिशन के तहत करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में इंटीग्रेटेड जिला पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा जींद, झज्जर और फरीदाबाद के बी.के. अस्पताल में 50-50 बेड के तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाये जाएंगे। जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही, राजकीय मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा।

शिशु मृत्यु दर में गिरावटः प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला के जिला अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) और इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। एसआरएस 2020 के अनुसार हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 28 है, जोकि 2013 में 41 थी। इसमें 13 अंकों की उल्लेखनीय रूप से कमी आई है।

नए स्वास्थ्य केंद्र तथा मेडिकल-पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती

- वर्तमान में मेडिकल कालेजों के अलावा 71 सिविल अस्पतालों 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 537 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2676 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । मार्च से अब तक 7 पी.एच.सी 5 सब सेंटर व एक सी.एच.सी का उद्घाटन किया गया है ।
- पंचकूला, पानीपत, नल्हड़, फरीदाबाद, सोनीपत व पलवल में मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित किये जा रहे है। प्रदेश में हैपेटाईटिस बी व सी की दवाइयां व जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।
- विभाग ने 954 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गए।
- 22 सेन्टरों में हिमोडायलिसिस सेवायें एवंम कार्डियोलॉजी सेवाएं, 4 कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट और 4 सिविल अस्पतालों में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि सेवायें 5 जिला नागरिक अस्पतालों में एमआरआई सेवायें मुहैया कराई गई।
- सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की नई पहल ।
- अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के नागरिक अस्पतालों को 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों का बनाया गया।
- 231 सर्जरी, 69 प्रकार के टेस्ट तथा 21 प्रकार की दन्त चिकित्सा के आप्रेशन मुफ्त। घर द्वार पर ही इलाज करने के लिए राज्य में 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट ।
- कोविड-19 टेस्ट के लिए राज्य में 26 सरकारी टेस्टिंग लैबोरेटरी बनाई गई।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 656 अस्पतालों (176 सरकारी एवं 480 निजी) को आयुष्मान भारत हरियाणा के साथ सूचीबद्ध किया जा चुका है।
- घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट दी गई। इस किट में डिज़िटल थर्मामीटर, थ्री लेयर मास्क, ऑक्सीमीटर, स्टीमर, एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल।
- सफीदों जिला जींद में एक सरकारी नर्सिंग कालेज का निर्माण करने का निर्णय। किराए के भवन में नर्सिंग कालेज शुरू।
- कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकूला में एक-एक व फरीदाबाद में 2 नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्य 194.30 करोड़ रु.की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर।
- गांव छायंसा, जिला फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है और चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में अस्पताल कार्यरत है।
- सरकार 172.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़, नूह परिसर में एक दंत महाविद्यालय स्थापित करने जा रही है।

आयुष

- पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के लिए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 19.87 एकड़ भूमि आयुष मंत्रालय भारत सरकार को स्थानान्तरित की जा चुकी है।
- गांव देवरखाना जिला झज्जर में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया जा रहा है तथा ओपीडी की प्रक्रिया शुरू।
- गांव मयड़, हिसार में लगभग 15 एकड़ जमीन पर 50 बिस्तरों का अस्पताल खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है।
- बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल पट्टीकरा, नारनौल का निर्माण कार्य पूर्ण। अस्पताल में ओ.पी.डी./आई.पी.डी. की सुविधा शुरू।
- गांव अकेडा, नूह में 45.43 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा है।
- जिला अम्बाला के गांव चान्दपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा है।
- 407 आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हैल्थ एंड वेलनैस सेंटर अपग्रेड करने का निर्णय।
- 347 आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर का कार्य पूर्ण तथा अन्य को अपग्रेड का कार्य जारी।

भारत एक दिसंबर से एक साल के लिए जी-20 देशों के समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इस दौरान अलग-अलग विषयों पर देश के विभिन्न भागों में वर्किंग ग्रुप व अन्य कार्य समूहों सहित लगभग 200 बैठकें होंगी।

महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि प्रदेश के जिन स्कूलों, कॉलेजों में छात्रावास हैं, उनमें अनुसूचितजाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा।

» 'देसा में देश हरियाणा-जित दूध दही का खाणा' कहावत हुई चरितार्थ

» राज्य सरकार की खेल नीतियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक छाए खिलाड़ी

खेल - खिलाड़ी

संगीता शर्मा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों का एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि आज हरियाणा का दूसरा नाम 'मेडल की खान' बन चुका है। प्रदेश के खिलाड़ी लगातार ओलंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीत कर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल हरियाणा की संस्कृति में ही रचे-बसे हैं, इसलिए यहां के खिलाड़ियों ने 'देसा में देश हरियाणा-जित दूध दही का खाणा' की कहावत को चरितार्थ किया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ खेलों में आधे से ज़्यादा पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी अहमदाबाद में हुए 36वें नेशनल गेम्स में भी परचम लहराया है।

हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा का नाम विश्वपटल पर चमका रहे हैं। अनेक मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की है। दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि मंडल भी हरियाणा के खेलों के आधारभूत ढांचे, सुविधाएं और ईनाम राशि की जानकारी के लिए दौरा कर रहे हैं। खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी करके वर्ष 2022-23 में 540.50 करोड़ रुपए किया गया है।

खेल स्पर्धाओं मे सर्वाधिक पदक

टोक्यो ओलंपिक-2020 में देश के 126 प्रतिभागियों में से प्रदेश के 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के 1.3 प्रतिशत क्षेत्रफल व 2.09 प्रतिशत आबादी वाले हरियाणा का ओलंपिक खेलों में 50 प्रतिशत से अधिक पदक का योगदान रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश में प्राप्त 7 पदकों में से प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, इसके साथ ही देश की महिला हॉकी टीम जो चतुर्थ स्थान पर रही, इस टीम में प्रदेश की 9 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो पैरालम्पिक-2020 में देश के 54 प्रतिभागियों में प्रदेश के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा देश को प्राप्त 19 पदकों में 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 2 कांस्य कुल 6 पदक राज्य के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा 2 खिलाड़ियों द्वारा चतुर्थ स्थान प्राप्त किया गया है। टोक्यो ओलम्पिक व पैरालमपिक 2020 के खिलाड़ियों को कुल 52.65 करोड़ रु. के नकद पुरस्कार वितरित किए गए।

हाल ही में बर्मिंघम में सम्पन्न हुए कॉमनवैल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में से 17 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। भारत के 1.3 प्रतिशत क्षेत्रफल व 2.09 प्रतिशत आबादी वाले हरियाणा का ओलम्पिक खेलों में भी 50 प्रतिशत से अधिक मेडल का योगदान रहा है। हरियाणा सही मायनों में खेलों की सोने की खान बनने की ओर अग्रसर है।

> राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही आज हरियाणा की खेलों में ऐसी पहचान बनी है कि अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। राज्य के खिलाड़ी इसी प्रकार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा और भारत का नाम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहेंगे। राज्य सरकार निरंतर खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
>
> **-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

खेलो इंडिया यूथ गेम्स

आज हरियाणा खेल क्षेत्र में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुका है। इसी के फलस्वरुप हाल ही में पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021 का सफल आयोजन कर हरियाणा ने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 अंडर-18 (लड़के एवं लड़कियों) का आयोजन 4 जून से 13 जून, 2022 तक भिन्न-भिन्न 25 खेलों में पंचकूला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) तथा दिल्ली में किया गया। इन खेल प्रतियोगिताओं में लगभग 8,500 खिलाड़ी/आफिसियल्ज ने भाग लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 का शुभारंभ देश के गृहमंत्री माननीय अमित शाह द्वारा किया गया। इन खेलों में प्रदेश के 518 लड़के एवं लड़कियों ने भाग लिया। इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 52 स्वर्ण, 39 रजत तथा 46 कांस्य कुल 137 पदक प्राप्त करके ओवरआल चैंपियन रहे। जनवरी, 2020 में गुवाहटी में 20 खेलों में आयोजित हुए खेलों इण्डिया यूथ गेम्ज-2020 में राज्य के 677 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने 200 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया।

खेल नर्सरियां स्थापित

हरियाणा सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। इस कड़ी में प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां चलाई जाएंगी। 500 नर्सरियां विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर तथा 600 खेल नर्सरियां सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल अकेडमियों, निजी खेल प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इन नर्सरियों में तैयार खिलाड़ियों को ग्रेड अनुसार छात्रवृत्ति, अनुबंधित प्रशिक्षकों को मानदेय तथा संबंधित शिक्षा संस्थाओं को ग्रेड अनुसार सामान के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। खिलाड़ियों की खुराक राशि 250 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2022 से 400/-रुपए प्रति खिलाड़ी, प्रतिदिन की गई है। स्कूल एवं कालेज के सामान्य खिलाड़ियों को एस.सी. खिलाड़ियों के समान छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पहली नवंबर, 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किये ऐप 'खेलो हरियाणा' के माध्यम से खिलाड़ी खेलों से संबंधित हर जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। मोरनी में मिल्खा सिंह साहसिक खेल एकेडमी भी स्थापित की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक गांव में एक-एक युवा कल्ब स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य मे अब तक 4912 गांवों में युवा क्लबों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में चार अनुसूचित खिलाड़ी खेल छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं। अंबाला मे खेल छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद में खेल छात्रावास के निर्माण का कार्य चल रहा है।

> राज्य के खिलाड़ियों ने हर खेल में अपना परचम लहराया है। कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स व हॉकी में खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। राज्य में खेल, खिलाड़ियों व आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें नकद पुरस्कार से सम्मानित व नौकरी में आरक्षण देकर हौसलाअफजाई की जाती है।
>
> **-संदीप सिंह, खेल एवं युवा मामले मंत्री, हरियाणा**

खिलाड़ियों को रोज़गार

सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी पॉलिसी -2013, 2014 (संशोधित), 2018 व 2021 (संशोधित) कुल 61 खिलाड़ियों की नियुक्ति की गयी है। सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिल विधान सभा में पास हो चुके इस एक्ट की अधिसूचना जारी की जा रही है। राज्य के सभी योग्य खिलाड़ियों को सभी श्रेणियों की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्रेणी 'घ' के लिए 10 प्रतिशत। श्रेणी क, ख तथा ग का आरक्षरण वित्त विभाग द्वारा समाप्त किया है, किंतु श्रेणी 'ग' के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने बारे कार्यवाही जारी है।

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार

» सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को अधिकतम नकद पुरस्कार तथा सुविधाएं देने में पूरे देश में उत्तम है।

» ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है।

» ओलंपिक खेलों हेतू चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि में से प्रशिक्षण तथा खुराक हेतू अग्रिम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है।

» पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह प्रतिभागिता करने पर सामान्य खिलाड़ियों की भांति नकद पुरस्कार की बराबर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

» डेफलंपिक खेल-2022 में राज्य के 15 प्रतिभागी खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1.20 करोड़, कांस्य पदक के लिए 40 लाख तथा प्रतिभाग खिलाड़ियों को 2.50 लाख रु. की दर से कुल 5.83 करोड़ रु. की नकद ईनाम राशि प्रदान की गई। इन खेलों में खिलाड़ियों द्वारा 4 स्वर्ण तथा 2 कांस्य पदक प्राप्त किये।

» विश्व की 10 अधिकतम ऊंची/जटिल चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले खिलाड़ियों को 5.00 लाख रुपए का नकद ईनाम तथा ग्रेड-सी का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया है।

» आगामी एशियन/पैरा एशियन तथा कॉमनवैल्थ/पैरा कॉमन वैल्थ खेलों के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 2.50 लाख रुपए की अग्रिम तैयारी राशि प्रदान की जाएगी।

» ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डीज का मानदेय 5,000/-रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 20,000/-रु. प्रतिमास किया गया है।

» तेनजिंग नोर्गे अवार्डी को 20,000/-रुपए की तरह ही भीम अवार्डी को भी 5,000/- रुपए प्रतिमास मानदेय दिया जा रहा है।

» गत 4 वर्ष से लंबित भीम अवार्ड 52 योग्य अवार्डीज को महामहिम राज्यपाल के करकमलों से प्रदान किया गया, जिसमें प्रति अवार्डी 5.00 लाख रुपए नकद, 01 ब्लैजर, टाई/स्कार्फ, स्क्रोल तथा भीम प्रतिमा सहित कुल 2.60 करोड़ रुपए के नकद राशि दी गई।

हरियाणा पुलिस को प्रगति डैशबोर्ड में जून -जुलाई, 2021 में 100 अंकों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रगति डैशबोर्ड में सितंबर, 2021 से दिसंबर, 2021 तक लगातार हरियाणा पुलिस ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्रदेश में रोज़ाना की 1000 से अधिक कॉल्स प्राप्त हो रही है जिन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अब तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचाने में सफलता हासिल हुई है।

विकास के मार्ग

» औद्योगिक विकास के अनुकूल बन रहे सड़क एवं रेलवे मार्ग

» शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों की सुगमता के लिए बढ़ाया बजट

प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मनोहर सरकार ने सड़क मार्गों पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र सरकार की मदद से भी अनेक हाईवे निकाले गए हैं और निकाले जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस तरह के अनेक मार्ग बनाए गए हैं। गुरुग्राम क्षेत्र को तो दुबई की तर्ज पर विकसित करने की बात चल पड़ी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सूबे में जितने सुगम मार्ग होंगे उतना ही ज्यादा उद्योग विकसित होगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वे इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में 6192 करोड़ रुपए की लागत से 9422 कि.मी. लम्बी सड़कों का सुधार किया जा चुका है तथा 796 करोड़ रुपए की लागत से 905 कि.मी. लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। 33 फीट से अधिक चौड़ाई वाले सभी राजस्व मार्गों को मेटल्ड से पक्का किया जाएगा।

नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत सरकार के कार्यकाल-2 के दौरान 1065.71 कि .मी. लम्बी सड़कों का सुधार 590.33 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 318.67 करोड़ रुपए की लागत से 446.55 किमी लम्बी 50 सड़कों और एक पुल का कार्य प्रगति पर है।

टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना, नारनौन्द, चीका और सोनीपत शहर के बाईपास निर्माण के लिए 950.12 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। पिंजौर, टोहाना व हथीन बाईपास का कार्य प्रगति पर है।

योजना के तहत 383.58 करोड़ रुपए की लागत से 688.94 किलोमीटर की लंबाई वाले 83 सड़क, 549.51 करोड़ रुपए की लागत से 1216.95 किलोमीटर की लंबाई वाली 120 सड़क के लिए मंजूरी हो चुकी है। जबकि 771.68 करोड़ रुपए की लागत से 1722.80 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है तथा 183.08 किलोमीटर की लंबाई का कार्य जिसकी अनुमानित लागत 89.71 करोड़ रुपए है प्रगति पर है।

रेलवे, ऊपरगामी/भूमिगत पुल

राज्य में नई रेलवे लाइनों की हिस्सेदारी के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 56 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 16 रेलवे ऊपरगामी पुल/रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य 156.31 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया जा चुका है व 40 रेलवे ऊपरगामी पुल/ रेलवे भूमिगत पुलों तथा 5 अन्य प्रमुख पुलों का निर्माण कार्य 1422.19 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है।

रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन का कार्य भी शुरू हो चुका है और इसके अगामी दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण के लिए 366.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। कुल अनुमानित लागत 844.15 करोड़ रुपए है। शेष बची हुई भूमि को खरीदने का कार्य हरियाणा चकबंदी अधिनियम, 2017 के तहत 31 मई 2022 तक केवल 3 मरला छोड़कर पूर्ण कर लिया गया है।

रोहतक शहर में ट्रैक को ऊँचा उठाने का कार्य भारतवर्ष में पहली बार हुआ जिसका कार्य मार्च, 2021 में पूर्ण हो चुका है।

हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर, पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा (130 कि.मी. विद्युतीकृत नई बी.जी. डबल लाईन परियोजना) को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसकी अनुमानित लागत 5617 करोड़ होगी। रेलवे एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण की प्र्रि या शुरू कर दी गई है। प्राथमिकता खण्ड मानेसर से मौजूदा पाटली रेलवे स्टेशन तक निर्माण का कार्य आबंटित किया जा चुका है। जिसकी अनुमानित लागत 175.80 करोड़ रुपए है।

करनाल-यमुना नगर नई रेलवे लाईन (61 कि.मी) की डी.पी.आर. रेलवे को भेज दी गई है। कुरुक्षेत्र शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एलिवेटेड रेलवे लाईन की परियोजना का कार्य 265.18 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर तथा जून, 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

कैथल शहर में मौजूदा नरवाना- कुरुक्षेत्र लाईन पर एलिवेटेड रेलवे लाईन की परियोजना के लिए अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इससे 3 लेवल 'क्रॉसिंग बंद हो जाएंगे। परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है और इसे मंजूरी के लिए रेलवे को दिनांक 22.09. 2020 को भेज दिया गया है। इसकी लागत 191.73 करोड़ रुपए है।

बजट 2022- 23 में प्रावधान

वर्ष 2022-23 में सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए कैपिटल स्कीम के अंतर्गत 2090.37 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है व मरम्मत योजना के अंतर्गत सड़कों व पुलों के लिए 467.51 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

खोजकीपुर के पास यमुना पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर। इस पर 87.08 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नब्बे करोड़ रुपए की लागत से जठलाना के पास यमुना पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भिवानी-खरक जिसमें भिवानी बाई पास शामिल है, सड़क को चारमार्गीय बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर 247.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शीला बाईपास रोहतक पर चारमार्गीय फ्लाईओवर के निर्माण जिसमें रोहतक-खरखौदा-दिल्ली बॉर्डर सड़क पर नहर और भालोट सब-ब्रांच सहित चारमार्गीय पुलों का निर्माण रोहतक शहर में 74.00 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदन किया जा चुका है व कार्य प्रगति पर है इसके अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। करनाल-मेरठ सड़क को 105.49 करोड़ रुपए की लागत से छह मार्गीय/ चार मार्गीय कार्य पूर्ण हो चुका है।

सुरक्षित यातायात

» राज्य परिवहन के बेड़े में 2019 से जून, 2022 तक 150 मिनी बसें तथा 18 सुपर लग्जरी बसें शामिल की गई।

» परिवहन कर्मचारियों का वर्दी भत्ता गर्मियों की वर्दी के लिए 1350 रुपए प्रतिवर्ष तथा सर्दियों की वर्दी के लिए (तीन वर्ष में एक वर्दी) 1,450 रुपए किया गया।

» हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालकों के लिए सात नए चालक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए गए हैं। अब राज्य परिवहन विभाग द्वारा संचालित चालक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 22 हो गई है।

» बसों में कैंसर पीड़ित के साथ एक सहयोगी को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध।

» सकल लागत माडल पर 124 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना तैयार। जिसमें 12 मी. लम्बाई वाली एसी बसों की 70 इलेक्ट्रिक बसों और 9 मी. लम्बाई वाली 54 साधारण बसें शामिल हैं।

» किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत बस किराए पर। 21.03.2021 तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 538 साधारण बसों का संचालन है।

» छात्राओं को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक 150 किमी दूरी तक मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध है। महिला एवं छात्राओं के लिए 213 मार्गों पर 181 विशेष सेवा बसें चलाई जा रही हैं।

» विभाग ने सस्ती, सुरक्षित, टिकाऊ परिवहन सेवा के लिए ई-टिकटिंग, ऑपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस ऑन बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल लागू करने की पहल की है।

» वरिष्ठ नागरिकों (महिला 60 वर्ष एवं पुरुष 65 वर्ष से अधिक की आयु) को राज्य की सीमा के अन्दर बस किराए में दी जा रही 50 प्रतिशत छूट को बढ़ा कर अन्य राज्यों के गन्तव्य स्थान तक कर दिया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पंजीकरण और जांच-पड़ताल की सुविधा के लिए प्रदेश में कुल 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किये गए हैं।

युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए अनुग्रह राशि निःशक्तता के आधार पर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए की गई।

महिला एवं बाल विकास

> हरियाणा की महिलाओं ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। इसके चलते हरियाणा में बेटियों व महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए एक नई योजना 'हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना' के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है।
>
> **-कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा**

महिला परिवार की धुरी होती है और बच्चों के लालन-पालन व परिवार को सुचारू रूप से चलाने में विशेष योगदान होता है। इसलिए महिला के पौष्टिक खान-पान, शिक्षा व सम्मान की ओर विशेष ध्यान देना हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई। महिलाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने खंड, जिला व प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। उनके पुरस्कार राशि में भी समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है। वर्ष 2021-22 में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 1,508.30 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,338.26 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है तथा वर्ष 2022-23 में विभाग का बजट 2,019.24 करोड़ रुपए है ।

लिंगानुपात में सुधार

राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लड़की के जन्म व कन्यादान में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लड़कियों के पोषक आहार का प्रबंध व उच्च शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात तथा महिला के सशक्तिकरण के लिये पानीपत में 22 जनवरी, 2015 से ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के माध्यम से जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 876 था अब माह मई, 2022 में बढ़कर

920 हो गया है। ''आपकी बेटी हमारी बेटी योजना'' के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी परिवारों को दूसरी एवं तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि जन्म के एक वर्ष के अंदर बच्ची के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में एकमुश्त जमा करवाई जाती है तथा बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण/अविवाहित होने पर लगभग एक लाख रुपए उसके उपयोग के लिए दी जायेगी।

महिलाओं को सम्मान

सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार योजना के तहत भी महिलाओं को नकद ईमान से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय प्रदर्शन करने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। महिलाओं के विकास के लिए 'हरियाणा कन्या कोष' स्थापित किया गया। महिलाओं के मान-सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाईफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, विशिष्ट उपलब्धियों पर खेल पुरस्कार, सरकारी व सामाजिक सेवा पुरस्कार दिये जाते हैं। महिला दिवस 8 मार्च, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिला हैल्पलाईन-181 का व्हाटसएप नंबर 9478913181 लान्च किया गया।

आंगनवाड़ी केंद्र हुए अपग्रेड

बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में आंगनवाड़ी केंद्रों का विशेष योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए 4 हजार प्ले-वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है तथा 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल में अपग्रेड किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के तहत 3 एलईडी लाईट व 2 पंखों की व्यवस्था की जाएगी। प्रथम चरण में 5,108 आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ दिया गया है। 22 जिलों में आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 1,03,848 ग्रोथ मोनिट्रिंग उपकरण सप्लाई कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी कार्यकर्ता का मानदेय फरवरी, 2018 से 10 वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव रखने वाली व 10 वर्ष तक का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय क्रमशः 12,661 रुपए व 11,401 रुपए तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय भी 11,401 रुपए तथा सहायिकाओं का 6,78 1 रुपए कर दिया गया है।

हरिहर नीति

राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चें जिनका कोई अभिभावक नहीं है या किसी कारणवश उनके अभिभावकों ने उनको छोड़ या त्याग दिया है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं है तथा जिन बच्चों ने 5 वर्ष की आयु से पहले (छोड़े गए बच्चे) तथा 1 वर्ष की आयु से पहले (त्यागे हुए बच्चे) बाल देखरेख गृहों में प्रवेश पा लिया हो और उन्हें रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है ऐसे बच्चों को शैक्षिक, वित्तीय और रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2021 को 'हरिहर' योजना अधिसूचित की है।

24 घंटे बिजली

» प्रदेशवासियों का सपना हुआ साकार
» बिलों की समय पर हो रही अदायगी

इतिहास गवाह है, जब भी सूबे की समस्याओं का जिक्र होता था तो बिजली, पानी और सड़क का नाम लिया जाता था। वैसे भी जहां-तहां के विकास का आकलन होता है हो तो इन्हीं तीन पहलूओं पर गौर किया जाता है। हरियाणा प्रदेश की मनोहरलाल सरकार ने अपने कार्यबल से इन तीनों पहलूओं का जिक्र खारिज कर दिया है। पर्याप्त बिजली, हर घर नल से जल और सड़कों का जाल अपने आप सूबे के विकास की कहानी बयां कर रहे हैं।

24 घंटे बिजली। आठ बरस पूर्व अलबत्ता तो यह बात होती नहीं थी, अगर होती थी तो एक सपना सा लगता था। बेकार की बात लगती थी, ख्याली पुलाव लगता था। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से पूर्व बिजली पर कोई कार्य नहीं हुए, हुए लेकिन वे इतने नाकाफी थे कि उनका जिक्र इतनी मजबूती के साथ नहीं किया जा सकता जितना आज। याद है तीन-तीन दिन बाद बिजली आने का नंबर होता था। वह भी कुछ घंटे के लिए। शहरी क्षेत्र में व्यवस्था थी कि आज दिन का नंबर है, कल रात का। उद्योग-धंधे भी उसी के अनुसार संचालित होते थे। कई बार तो गांवों में सप्ताह-सप्ताह भर बिजली नहीं आती थी। गर्मी के दिनों में हाथ में पंखा लेकर इधर-उधर डोलना या पेड़ के नीचे बैठना आम बात थी। आज वे नजारे कहीं दिखाई नहीं देते। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त कोई उपभोक्ता सरकार या बिजली वालों को कोसता भी नहीं था। आज अगर किसी कारणवश एक घंटा बिजली नहीं होती है तो लोग राजनीतिक चर्चा करने लग जाते हैं।

प्रदेश की मनोहर सरकार में वे सारे हालात इतिहास बन गए हैं। अधिकांश गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। लाइन लॉस भी कम हुआ है तथा दोनों निगम मुनाफे में हैं। यह राज्य सरकार का सुशासन ही है कि उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल भरने की आदत डाल ली है। बिलों की समय पर अदायगी न होने से उपभोक्ता अपनी 'हीणी' मानने लगा है। राज्य सरकार ने भी उपभोक्ताओं का पूरा सम्मान किया है तथा बिजली की उपलब्धता के लिए खूब कार्य कराए हैं।

सब स्टेशन बनाए गएी: 2014 से अब तक प्रसारण नेटवर्क को सदृढ़ करने के लिए 3704.74 करोड़ रुपए की लागत से 58 नए सब-स्टेशनों की स्थापना तथा 531 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि के साथ 1908 कि.मी. की प्रसारण लाईनें जोड़ी गईं हैं।

अगले 5 वित्त वर्षों में 2027-2028 तक प्रसारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, 4388.04 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 48 नए सब स्टेशन बनाने, 209 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने तथा 3705.75 सर्किट कि.मी. प्रसारण लाइन बिछाने का लक्ष्य है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 11091.97 करोड़ रुपए खर्च किये गये। प्रदेश में 51956 नये ट्रांसफार्मर लगाए गये हैं।

नए ट्यूबवैल कनैक्शन जारी: दिसम्बर, 2018 तक आवेदित सभी 84,537 नए ट्यूबवैल कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर फाइव स्टार रेटिड एनर्जी एफिसिएंट मोटर पंपसेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक 30441 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

जुर्माना राशि माफ :सरचार्ज माफी योजना-2019 के तहत 1,12,300 किसानों के बिजली बिलों की 23 करोड़ 93 लाख रुपए की जुर्माना राशि माफ की गई है। इतना ही नहीं 20962 घरेलू, कृषि एवं एच.टी. और औद्योगिक या गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 23 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि माफ की गई।

प्रदेश में वितरण लोसिस वर्ष 2015-16 में 30.3 प्रतिशत थे, जो कि वर्ष 2021-22 के अन्त तक घटकर 13.8 प्रतिशत तथा 11.01 प्रतिशत रह गए हैं। बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने तथा बिजली चोरी रोकने के लिए 'फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम' की शुरुआत की गई ।

खतरनाक लाइनें हटाई गईः घरों, कालोनियों, तालाबों तथा स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2539 खतरनाक लाइनें हटाने का निर्णय । उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए आनलाइन पोर्टल की शुरुआत।

किसानों को सस्ती दरों पर बिजलीः कृषि की उत्पादन लागत कम करने और कृषि गतिविधियों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली सब्सिडी के लिए वर्ष 2022-23 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 34,600 करोड़ के ऋण में से 25,950 करोड़ रुपए वहन किए गए।

5622 गांवों को 24 घंटे बिजलीः म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद व रेवाड़ी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। इस योजना के तहत 1,510 फीडर के 5622 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

उद्योग चलाने पर रियायती दरः पीक आवर में बिजली की खपत को कम करने के लिए नवम्बर, 2021 से मार्च 2022 तक रात (रात्रि 9 बजे से प्रातः 5:30 बजे तक) उद्योग चलाने पर रियायती दरों पर बिजली अब उपलब्ध रहेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रदान की प्री-पेड सुविधा है तथा बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए 1912/18001801550 टोल फ्री नम्बर की सुविधा उपलबध कराई गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा

पारम्परिक ऊर्जा की निर्भरता कम करने तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सोलर नीति, 2016 लागू की गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने घरों के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। 30 जून 2020 तक राज्य में 183.22 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट छतों के ऊपर लगाए जा चुके हैं। अनुदान कार्य म बिजली वितरण निगम द्वारा चलाया जा रहा है। सरकारी भवनों पर 6 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई गई हैं।

330 पंजीकृत गौशालाओं में 9.19 करोड़ की लागत से 2.0 मेगावाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाए जा चुके हैं तथा 150 गौशालाओं में चालू वर्ष में लगाए जायेंगे। प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत ऋण लेकर 50000 सोलर पंप लगाने की परियोजना शुरू की गई है।

पराली आधारित बायोगैस परियोजनाः पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में कुल 49.8 मेगावाट क्षमता की पराली आधारित बायोमास परियोजनाएं स्वीकृत हैं। कैथल तथा कुरुक्षेत्र की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं ।

क्लास वन अधिकारी से सीधा आई.ए.एस बनने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को प्रदेश की ओर से भेजे जाने वाले नामों के लिए वर्ष 2020 से हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल साधनों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की प्रदायगी हेतु 'नागरिक संसाधन सूचना विभाग', 'विदेश सहयोग विभाग', 'आवास विभाग' और 'एम.एस.एम.ई. विभाग' का गठन किया गया है।

पर्यटन

» गुरुग्राम और नूह में स्थापित होगा सफारी पार्क
» स्टे होम पॉलिसी से बढ़ रहे रोज़गार के अवसर

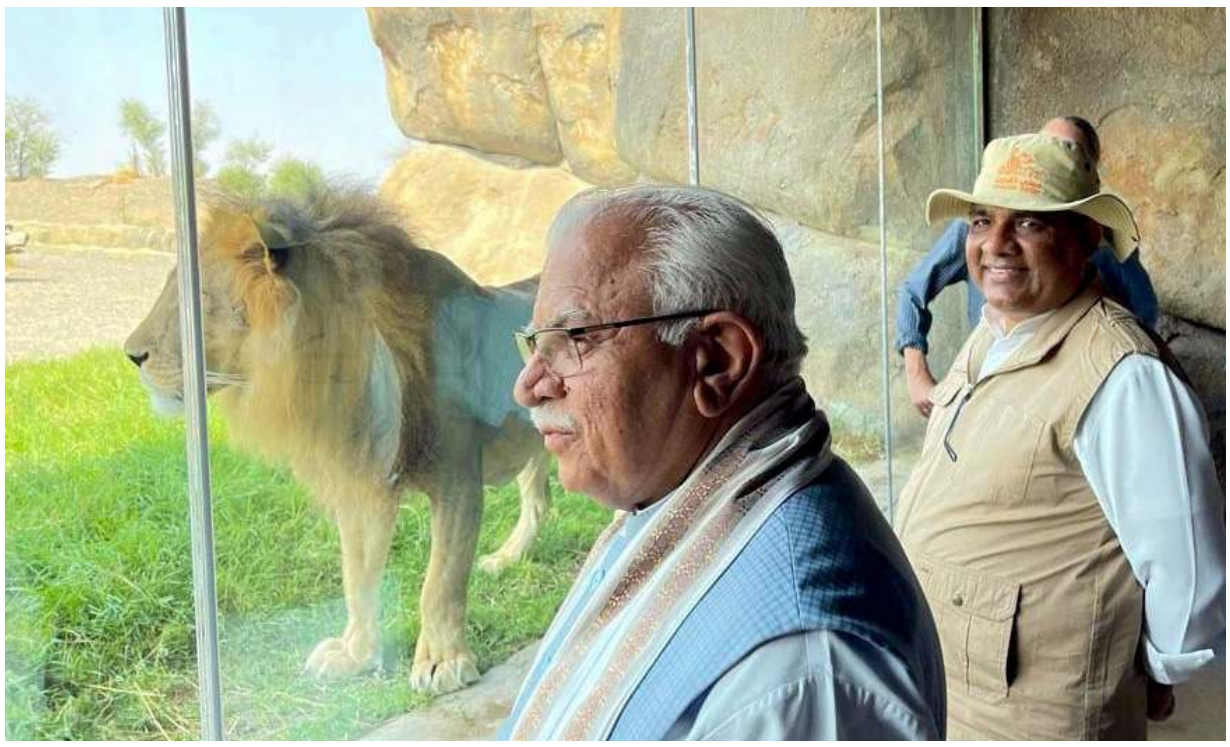

उत्तर भारत में स्थित हरियाणा एक धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां जहां आस्था का प्रतीक कुरुक्षेत्र नगरी है तो वहीं, पानीपत के ऐतिहासिक स्थल व मोरनी के रोमांचकारी पर्यटन स्थल भी यकायक सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। यह पैरा सिलिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग जैसे साहसिक खेलों के लिए एक आदर्श जगह है। यहां कई मनोरंजन पार्क और थीम पार्क भी हैं। कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती फेस्टिवल व फरीदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला भी देशी व विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है।

गुरुग्राम और नूह की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10 हजार एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है जो फरवरी 2022 में खोला गया था जिसका क्षेत्रफल करीब दो हजार एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क आकार का पांच गुना होगा और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम, एवियरी/बर्ड पार्क, बिग कैट्स के चार जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु-पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक अंडरवाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स/विजिटर/टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन/बायोमेस, इक्वाटोरियल/ट्रॉपिकल/कोस्टल/डेजर्ट इत्यादि होंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी की अपार संभावनाएं हैं। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिए क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया और इस तरह के पार्क की स्थापना की तकनीकी व्यवहार्यता से सहमत हो गया है।

> हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की एक संयुक्त परियोजना होगी। एक योजना के तहत केंद्र सरकार भी हरियाणा को इस परियोजना के लिए फंड मुहैया करेगी। परियोजना के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ईओआई मंगाई गई थी और ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वे अब पार्क के डिजाइन, निर्माण की निगरानी और संचालन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
>
> **-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री**

पर्यटन भी- तीर्थाटन भी

राज्य सरकार द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए अथक कार्य किए गए हैं। कुरुक्षेत्र को एक मुख्य पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने 97.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति में से 77.87 करोड़ रुपए की राशि, सूचना केंद्र, गैजिबो, पार्किंग, साईनेज बोर्ड, बेंचों, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों, और घाट इत्यादि के निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। 30 जून, 2022 को कुरुक्षेत्र में गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में भगवान श्रीकृष्ण की 40 फीट ऊंची प्रतिमा विराट स्वरूप का अनावरण किया गया। यह करीब 35 टन वजनी मूर्ति 85 फीसद तांबे समेत चार तरह की धातुओं के मिश्रण से बनी है। इसके विशाल रूप में भगवान श्रीकृष्ण के नौ रूपों को दर्शाया गया है।

हैरिटेज सर्किट रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल

महेंद्रगढ़-नारनौल सर्किट के अंतर्गत महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए व रानी महल, बावड़ी के आंतरिक व बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए व माधोगढ़ किले को छोड़कर किले के आस-पास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 29.61 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना पर कार्य शुरू किया गया।

साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा

नाडा साहिब गुरुद्वारा, पंचकूला व माता मंसा देवी मंदिर के विकास हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना पर निर्माण कार्य जारी है। पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए टिकरताल, मोरनी हिल्स को साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जैट स्कूटर जैसी ऐरो स्पोर्ट्स और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां व्यावसायिक रूप से चालू की गई। 52.32 करोड़ रुपए की एक डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) आदि बद्री के विकास हेतु मामला पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

स्टे-होम पोलिसी

हरियाणा के ग्राम जीवन व खान-पान से देश व विदेश के पर्यटकों से रु-ब-रु करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टे-हॉम पोलिसी को मंजूरी दी है ताकि विशेष महत्व वाले स्थानों पर पर्यटकों को अपने-घर पर ही स्टे करवाया जा सकें। अब गृह स्वामी इस योजना के तहत पर्यटकों को व्यावसायिक आधार पर कमरों /आवास की पेशकश कर सकते हैं। पर्यटकों के पास होटलों के अलावा एक अन्य विकल्प होगा जहां वे घरों में स्थानीय परिवारों के साथ रह कर देशज संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक ओर स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वहीं पर्यटक ग्रामीण जीवन शैली व खान-पान का आंनद ले सकेंगे। मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्टस को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्टे-होम पोलिसी के तहत 30 से अधिक लाइसैंस जारी किए गए हैं और वहां पर पर्यटक रूक रहे हैं। मोरनी हिल्स के लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और एक नया बदलाव महसूस किया जा रहा है। सिंधुघाटी सभ्यता का स्थल रहा हिसार के राखीगढ़ी में भी स्टे-होम पोलिसी के तहत लाइसैंस देने की घोषणा गत दिनों मुख्यमंत्री ने की है।

-संगीता शर्मा

पर्यावरण

सघन वन रोपण

» अक्तूबर, 2014 से वर्ष 2021-22 तक 14.36 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 2200 गांवों में 2 करोड़ सघन पौधारोपण किया जाएगा।
» यमुना तथा घग्गर नदियों के क्षेत्रों में भूमि कटाव, जल संरक्षण एव नदियों के जीर्णोद्धार के लिए नदियों के साथ लगते गांवों की विभिन्न प्रकार की भूमियों पर 20.03 लाख पौधे रोपित किए गए हैं।
» पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के सभी स्कूलों के छठीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक 66.07 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 19 लाख पौधे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
» जल शक्ति अभियान के तहत आने वाले 19 जिलों में गहन वनीकरण गतिविधियां की जा रही हैं। इन जिलों में रोपण के लिए ग्रामीण विकास विभाग को वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक 90.50 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वर्ष 2022-23 में 29 लाख पौधे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वायु एवं जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति के इन दोनों मूल कारकों का स्वच्छ होना जीवन के लिए निहायत जरुरी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य हुए हैं। न केवल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं बल्कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना तथा अमृत सरोवर योजना के जरिए पानी बचाने के भी प्रयास किए गए हैं। वायु में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो इसके लिए उद्योग एवं कृषि क्षेत्र से निकलने वाले धुएं पर अंकुश लगाने की गंभीर कोशिशें हुई हैं। पर्यावरण को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में पौधागिरी पर आंदोलन सरीखे कार्य हुए हैं।

सरकार हर वर्ष पौधे लगाती है। इस वर्ष भी 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में हरियाणा का वन क्षेत्र 7.14 प्रतिशत है। इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाना बड़ा जरूरी है और यह जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। हरियाणा सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को एक एकड़ में बाग लगाने पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ तीन साल तक मुआवाजा देने की योजना भी शुरू की है।

वृक्षों के लिए शुरू की पेंशन: हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है।

तालाबों पर त्रिवेणी: प्रधानमंत्री ने आजादी के 'अमृत महोत्सव' के अवसर पर 'अमृत सरोवर' की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की है। जोहड़ हरियाणा के गांववासियों की जीवन रेखा है और इनको पूजा जाता है। जोहड़ों पर छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। अतः इसी कड़ी में राज्य के 22 जिलों के 2200 जोहड़ों पर बड़, पीपल, नीम और पिलखन के पौधे रोपित किए गए।

हरियाणा में जमीनी स्तर पर हुए कार्यः एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि मनोहर लाल की भावनात्मक रूप से कार्य करने और समस्याओं का स्थाई हल निकालने के लिए योजनाएं तैयार करने की छवि बनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने के बाद हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितना काम हुआ है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में इससे पहले कभी भी तीव्र गति से न तो योजनाएं बनी, न ही जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हो पाई।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com